Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
(A National Multidisciplinary bi-lingual Quarterly Double Blind Open Access Peer Reviewed Refereed Journal)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: (Cosmos: 7.866 & I2OR: 5.675) Volume 16, No. 03, July-September, 2026, pp. 141-146

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

आशीष कुमार यादव*

सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, गोविंदगढ़, अलवर, राजस्थान।

*Corresponding Author: yadavashish22876@gmail.com

Citation: *यादव, आशीष (2026). भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 16(03), 141–146.*

ABSTRACT

भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर ली है। इन्होंने देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया है: जहाँ पहले एक ही पार्टी का शासन होता था, वहीं अब कई पार्टियों वाली गठबंधन सरकारें आम बात हो गई हैं। ये पार्टियां क्षेत्रीय और भाषाई पहचान, जातिगत हितों, जातीयता और हर राज्य की खास विकास ज़रूरतों को हाईलाइट करती हैं, साथ ही डेमोक्रेटिक मूल्यों और फेडरलिज्म को भी मजबूत करती हैं। कांग्रेस पार्टी का दबदबा कम होने और पार्लियामेंट में कोएलिशन पॉलिटिक्स के बढ़ने के साथ यह बदलाव और तेज़ हो गया। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे क्षेत्रीय पार्टियाँ प्रतिनिधित्व बढ़ाती हैं, संघवाद को मज़बूत करती हैं और राजनीतिक सत्ता के बँटवारे को आकार देती हैं, साथ ही शासन–व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ भी खड़ी करती हैं। गठबंधन की रणनीतियों, संघीय व्यवस्थाओं और मौजूदा राजनीतिक हालात के विश्लेषण के ज़रिए, यह अध्ययन दिखाता है कि क्षेत्रीय पार्टियाँ भारत के असमान संघीय ढाँचे में अहम भूमिका निभाती हैंकृइनके पास वीटो पावर होती है और ये संरचनात्मक बफ़र (संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने वाले) के तौर पर काम करती हैं। राष्ट्रीय लोकतंत्र में बाधा डालने के बजाय, क्षेत्रीय पार्टियाँ भारत की विविधतापूर्ण, संघीय और प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था का एक ज़रूरी हिस्सा हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखा, जब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन की ज़रूरत पड़ी।

शब्दकोशः *क्षेत्रीय राजनीतिक, डेमोक्रेटिक, फेडरलिज्म, कोएलिशन पॉलिटिक्स।*

प्रस्तावना

संविधानिक संरचना और भारतीय संघवाद

भारतीय संविधान एक अनोखा संघीय ढांचा पेश करता है जिसे भारत के विविध समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है (साहा और डाकुआ, 2024)। इंडियन फ़ेडरलिज़्म के इस फ्रेमवर्क को कई जानकारों ने ''क्वासी–फ़ेडरल,'' ''कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज़्म,'' और ''सेंट्रलाइज़िंग टेंडेंसी वाला फ़ेडरेशन'' बताया है – इसने इंडिया में कोएलिशन पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है (साहा और डाकुआ, 2024)। हालांकि संविधान राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान करता है, लेकिन असल में भारतीय राजनीति का स्वरूप

* *Copyright © 2026 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

काफी हद तक क्षेत्रीय है (प्रसोभ, 2025)। भारत में भाषाओं, धर्मों, जातियों, जनजातियों और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता ने राज्य–केंद्रित राजनीतिक दलों के उदय और विकास के लिए एक स्वाभाविक माहौल बनाया है।

भारतीय संघवाद का विकास केंद्र–राज्य संबंधों के जटिल इतिहास को दर्शाता है, जिसमें राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक पहलू शामिल हैं (शर्मा, 2023)। 1947 में आज़ादी के बाद से, भारतीय राजनीति एक ही पार्टी के दबदबे वाली व्यवस्था से बदलकर बहु–दलीय गठबंधन व्यवस्था की ओर बढ़ गई है। इस बदलाव में क्षेत्रीय दलों ने अहम भूमिका निभाई है; उन्होंने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आवाज़ दी है और भारत के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्षेत्रीय दलों का उदय और महत्व

खासकर आज़ादी के बाद के दौर में, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भारत के बहु–दलीय लोकतंत्र की एक अहम पहचान बन गई हैं (नोरबू, 2026)। ये पार्टियां क्षेत्रीय पहचान, आत्म–निर्णय और स्व–शासन पर केंद्रित आंदोलनों से उभरी हैं, और साथ ही भारत के संघीय ढांचे में अपनी जगह बनाने के लिए भी काम करती रही हैं। यह बदलाव 1990 के दशक के बाद से खास तौर पर अहम हो गया है, जब वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण की लहरें भारतीय राजनीति को नया रूप दे रही थीं। आर्थिक सुधारों और सामाजिक–राजनीतिक बदलावों के इस दौर ने क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में ला खड़ा किया, जिससे भारतीय संघ में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई (देबनाथ, 2026)।

क्षेत्रीय पार्टियों का मुख्य काम भारतीय राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। ये पार्टियां स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि भारत के विविध राजनीतिक ढांचे में अल्पसंख्यकों और क्षेत्रीय हितों की बात सुनी जाए (प्रसोभ, 2025)। खास तौर पर, ये पार्टियां हाशिए पर मौजूद समुदायों को प्रतिनिधित्व देती हैं, राजनीतिक सत्ता का पुनर्वितरण करती हैं और भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करती हैं। पूर्वोत्तर भारत का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां क्षेत्रीय पार्टियों ने जातीय विविधता, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने और क्षेत्रीय महत्व से जुड़ी जटिलताओं को संभालने में अहम भूमिका निभाई है (नोरबू, 2026)।

गठबंधन राजनीति और भारतीय लोकतंत्र

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों से सीधे तौर पर जुड़ी सबसे अहम घटना गठबंधन की राजनीति का उदय है। 1954 में केरल में पहले राज्य–स्तरीय गठबंधन के गठन के बाद से, गठबंधन की राजनीति भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बन गई है (साहा और डाकुआ, 2024)। 1989 के बाद, गठबंधन की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख विशेषता बन गई – खासकर 2004–2024 के समय के दौरान, जिसने भारत के संसदीय ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव देखे (भूकर और दलाल, 2026)।

गठबंधन की राजनीति का ढांचा और कामकाज का तरीका बहुत जटिल होता है। ये गठबंधन चुनाव से पहले या चुनाव के बाद बन सकते हैं और ये विचारधारा या खास मुद्दों पर आधारित हो सकते हैं (देबनाथ, 2026)। गठबंधन की स्थिरता कई बातों पर निर्भर करती है, जिसमें लीडरशिप स्टाइल, विचारधारा की अनुकूलता, झगड़े का असरदार समाधान और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम शामिल हैं (तिर्की, 2024)। भारतीय गठबंधन राजनीति की एक खास बात यह है कि ये गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों को केंद्र स्तर पर फैसले लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने का मौका देते हैं।

2004–2014 के समय में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) ने एक डीसेंट्रलाइज़्ड, आम सहमति से चलने वाला तरीका अपनाया, जिसमें राज्य–स्तर की पार्टियों का पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया पर काफी असर था (भूकर और दलाल, 2026)। इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक

गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 2014 और 2024 के बीच एक केंद्रीकृत, बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण अपनाया; हालाँकि, 2024 के चुनावों के बाद गठबंधन पर निर्भरता एक बार फिर बढ़ गई है।

क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद एक जटिल और कई पहलुओं वाली घटना है जो भारत की आज़ादी से पहले से मौजूद है। भारत को अलग–अलग भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, समुदायों और धर्मों की भूमि के रूप में देखने से यहां की क्षेत्रीय पहचान की गहराई को समझना आसान हो जाता है (भट्टाचार्य, 2005)। आज़ादी के बाद का समय इस मामले में खास तौर पर उतार–चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें क्षेत्रवाद को अक्सर राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना जाता है। लेकिन, जानकारों और पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि भारत की एकता और अखंडता–खासकर जब यूगोस्लाविया या सोवियत यूनियन जैसे दूसरे मल्टी–कल्चरल यूनियनों से तुलना की जाती हैकृकाफी हद तक भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर की मजबूती और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की उसकी क्षमता की वजह से बनी रही है (भट्टाचार्य, 2005)।

वास्तव में, यदि सही ढंग से प्रबंधित किया जाए तो क्षेत्रवाद राष्ट्रीय सद्भाव के लिए हानिकारक नहीं है; बल्कि, यह इसके लिए अनुकूल भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब पॉलिटिकल सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल हो कि समय पर इलाके की मांगों को पूरा कर सके और इलाके की उम्मीदों को ज़ाहिर करने के लिए इंस्टीट्यूशनल रास्ते दे सके (भट्टाचार्य, 2005)। क्षेत्रीय पार्टियां इस तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं और क्षेत्रीय पहचान व राष्ट्रीय सद्भाव के बीच एक पुल का काम करती हैं।

विदेश नीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका

क्षेत्रीय दलों की भूमिका केवल घरेलू राजनीति तक ही सीमित नहीं है; उन्होंने भारत की विदेश नीति को भी काफी प्रभावित किया है। वैसे तो भारत की विदेश नीति पारंपरिक रूप से केंद्र सरकार के कंट्रोल में रही है, लेकिन राज्य सरकारें और क्षेत्रीय पार्टियां विदेश नीति को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में (चट्टोपाध्याय और देबनाथ, 2024)। 1990 के दशक में केंद्र में गठबंधन की राजनीति के उदय के साथ, यह उम्मीद की गई थी कि छोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी विदेश नीति बनाने में भूमिका निभाएँगी, हालाँकि असलियत ज़्यादा जटिल रही है (ब्लेरेल, 2019)। यह सुझाव दिया गया है कि नेशनल और रीजनल गठबंधन बनाने की प्रक्रियाओं के बीच तालमेल–जो फेडरल व्यवस्थाओं की खासियत है–नेशनल और रीजनल पार्टियों के बीच 'लॉक–इन' गठबंधन बनाता है जो विदेश नीति बनाने पर असर डालते हैं (ब्लारेल और विलिगेन, 2020)। 2008 के इंडिया–US न्यूक्लियर डील और 2009 से 2014 के बीच श्रीलंका के लिए पॉलिसी को लेकर फॉरेन पॉलिसी बनाने में रीजनल पार्टियों ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि, 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के तहत सेंट्रलाइजेशन का ट्रेंड तेज हो गया, लेकिन यह रीजनल पार्टियों को पूरी तरह से अलग करने में नाकाम रही (चटर्जी और मैत्रा, 2022)।

वित्तीय संघवाद और क्षेत्रीय दल

फिस्कल फेडरलिज्म के मामलों में रीजनल पार्टियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। फाइनेंस कमीशन के ज़रिए सेंटर–स्टेट रिलेशन का मैनेजमेंट और GST के ज़रिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम की रीस्ट्रक्चरिंग, ऐसे एरिया हैं जहाँ रीजनल पार्टियों ने अहम रोल निभाया है। 2014–2024 के समय में, भले ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी की बहुमत थी, लेकिन गठबंधन के साथियों–खासकर तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों–को कुछ फाइनेंशियल मामलों पर अपनी राय रखने का मौका दिया गया (भूकर और दलाल, 2026)।

सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय दल

क्षेत्रीय पार्टियों ने सामाजिक कल्याण नीति के क्षेत्र में भी काफी प्रभाव डाला है। हालांकि भारत ने अपनी वेलफेयर पहलों को बढ़ाया है, लेकिन यह बढ़ोतरी पॉलिटिकल रीजनलाइज़ेशन (टिलिन और परेरा, 2017) के ज़रिए फ़िल्टर हुई है। ब्राज़ील के उलट, जहाँ केंद्र सरकार ने गरीबी हटाने वाले प्रोग्राम पर ज़्यादा कंट्रोल किया है और ज़्यादा बराबर नतीजे हासिल किए हैं, भारत में सोशल प्रोविज़न का असर राज्य सरकारों पर निर्भर करता है, जिन्हें रीजनल पार्टियों का कंट्रोल होता है। इसका नतीजा यह होता है कि क्षेत्रीय स्तर पर काफी असमानताएँ देखने को मिलती हैं; कुछ राज्य बेहतर सामाजिक कल्याण सेवाएँ देते हैं, जबकि कुछ राज्य पीछे रह जाते हैं।

क्षेत्रीय दलों के सामने चुनौतियां

भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय पार्टियाँ जहाँ सकारात्मक भूमिका निभाती हैं, वहीं उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और वे खुद भी कई चुनौतियाँ खड़ी करती हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण, व्यक्ति–केंद्रित नेतृत्व, भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति, जाति–आधारित सक्रियता और अवसरवादी गठबंधन जैसे मुद्दे अक्सर क्षेत्रीय पार्टियों से जुड़े होते हैं (प्रसोभ, 2025)। इसके अलावा, मिली–जुली सरकारें अक्सर पॉलिसी बनाने में अस्थिरता और बेअसर होने से जूझती हैं, क्योंकि इसमें शामिल अलग–अलग पार्टियों के हित अक्सर एक–दूसरे से टकराते हैं।

गठबंधन की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी चुनौती पॉलिटिकल ब्लैकमेल की संभावना है, जिसमें छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर उनसे बहुत ज़्यादा रियायतें लेती हैं। इससे ऐसी मांगों और देश के हित से जुड़ी पॉलिसी के बीच तनाव पैदा हो सकता है (कुमार, 2026)। इसके अलावा, क्षेत्रीय पार्टियों के मज़बूत होने से कभी–कभी अलगाववादी रुझान को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां भाषाई, सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान बहुत मज़बूत होती है।

अंतर–पार्टी संबंध और संघीय समन्वय

क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को समझने के लिए, यह जानना ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य स्तर पर एक ही पार्टी या अलग–अलग पार्टियों की सत्ता होने से केंद्र–राज्य संबंधों पर क्या असर पड़ता है (गौतम सरकार, 2016)। आम तौर पर, जब दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी सत्ता में होती है तो बेहतर तालमेल देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी–कभी, अलग–अलग स्तरों पर अलग–अलग पार्टियों के होने से सहयोग भी बढ़ सकता है, खासकर तब जब ये पार्टियाँ एक–दूसरे का सम्मान करती हों।

भारत की संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से काम करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सक्षम और समर्पित नेतृत्व की आवश्यकता होती है (गौतम सरकार, 2016)। इसके लिए आपसी समझ और राजनीतिक सद्भावना की ज़रूरत होती है, खासकर उन मामलों में जहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों में टकराव हो सकता है। क्षेत्रीय पार्टियों की ताकतकृखासकर जब वे केंद्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा होंकृइस बात में निहित है कि वे केंद्र सरकार को क्षेत्रीय चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं।विविधता का प्रतिनिधित्व और समावेशन

क्षेत्रीय दलों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। भारत एक बहुत ही विविध देश है, और यह सुनिश्चित करना कि विविध समुदायों के हित राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिनिधित्व पाते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली की अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। छोटी राष्ट्रीय पार्टियां बड़े भौगोलिक इलाकों में अलग–अलग तरह के हितों का ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती हैं; इसके विपरीत, क्षेत्रीय दल विशिष्ट क्षेत्रों में गहराई से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार स्थानीय चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं (वनजा, 2024)।

छोटी रीजनल पार्टियां अहम भूमिका निभाती हैं, खासकर तब जब बड़ी पार्टियों को मेजॉरिटी पाने के लिए कोएलिशन बनाना पड़ता है। इससे छोटी पार्टियों को अपने–अपने इलाकों के हितों के लिए रिप्रेजेंटेशन पाने और वकालत करने का मौका मिलता है (मणिकंदन और वायट, 2019)। हालांकि, इस बात की भी संभावना है कि ये पार्टियां राष्ट्रीय सरकार से बहुत ज़्यादा रियायतें लेने के लिए अपनी स्थिति का फ़ायदा उठा सकती हैं।

2024 के चुनाव और क्षेत्रीय दलों की भूमिका

2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक अहम मोड़ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी–जिसने 2014 और 2019 में भारी बहुमत हासिल किया थाकृपूरी जीत हासिल करने में नाकाम रही। इसके बजाय, उसे तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और जनता दल (यूनाइटेड) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ा (प्रसोभ, 2025)। यह डेवलपमेंट भारतीय राजनीति में एक ज़रूरी मैसेज देता हैः रीजनल पार्टियां सिर्फ़ सपोर्टिंग एक्टर नहीं हैं, बल्कि भारतीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बैलेंस तय करने में सेंट्रल प्लेयर हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय राजनीति का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, न कि कोई अस्थायी घटना या ऐसी बाधा जिसे दूर करना हो। वे रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाते हैं, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, पॉलिटिकल पावर को बांटते हैं, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को आवाज देते हैं (प्रसोभ, 2025)। हालांकि वे कोएलिशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियल पॉलिसी कमियां ला सकते हैं, फिर भी वे भारत के अलग–अलग तरह के, फेडरल और रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल माहौल का एक ज़रूरी हिस्सा बने हुए हैं।

क्षेत्रीय पार्टियों की स्थायी स्थिरता केंद्र और क्षेत्रों के बीच सच्चे सहयोग पर निर्भर करती है (पांडा, 2025)। जब क्षेत्रीय पार्टियां लोकतांत्रिक और ज़िम्मेदार तरीके से काम करती हैं–भारत के विविध, संघीय और प्रतिनिधि राजनीतिक ढांचे के हिस्से के रूप मेंकृतो वे राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए नुकसान के बजाय ताकत का स्रोत बनती हैं (प्रसोभ, 2025)। भारत का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और केंद्र सरकार देश की विविधता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता और विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने अच्छे से मिलकर काम करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भट्टाचार्य, एच. (2005). भारत में संघवाद और क्षेत्रीयताः संस्थागत रणनीतियाँ और पहचान का राजनीतिक समायोजन। heiDOK (हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय)। https://doi-org/10-11588/heidok-00005500
2. भुकर, पी. के., और दलाल, आर. (2026). केंद्रीय स्तर पर भारत की गठबंधन सरकारों की राजनीति और नीतियाँः राष्ट्रीय–क्षेत्रीय पार्टी संबंधों की आलोचनात्मक समीक्षा (2004–2024)। TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research- https://doi-org/10-5958/2279&0667-2026-00002-7
3. ब्लेरेल, एन. (2019). गठबंधन की राजनीति और भारतीय विदेश नीति का निर्माणः एक नया शोध कार्यक्रम। India Review- https://doi-org/10-1080/14736489-2019-1703367
4. ब्लेरेल, एन., और विलिजेन, एन. वैन. (2020). क्षेत्रीय पार्टियाँ विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती हैं? भारत में बहु–स्तरीय गठबंधन सौदेबाजी से अंतर्दृष्टि। https://doi-org/10-1177/1354066120975072
5. चटर्जी, एस., और मैत्रा, एस. (2022). भारतीय विदेश नीति संघवाद के साथ कैसे तालमेल बिठाती हैः घटक राज्यों की भूमिका का एक केस स्टडी। Stosunki Międzynarodowe – International Relations- https://doi-org/10-12688/stomiedintrelat-17417-1

6. चट्टोपाध्याय, पी., और देबनाथ, बी. (2024). भारतीय संघवाद का बाह्यकरणः बांग्लादेश के प्रति भारत की नीति पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की भूमिका को समझना। India Review- https://doi-org/10-1080/14736489-2023-2295717

7. देबनाथ, एम. (2026). भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीतिः 1989 से आज के दौर तक का सफर। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। https://doi-org/10-36948/ijfmr-2026-v08i02-72261

8. गौतम सरकार, एस. (2016)। भारतीय संघवाद के बदलते हालातः राजनीतिक दलों की भूमिका। https://www-semanticscholar-org/paper/e1e44e1677f11f0159b1f33871a9abf26cf18ca6

9. कुमार, ए. (2026)। गठबंधन सरकारें और चुनावी गठबंधनः भारतीय संसदीय राजनीति में इनके तौर–तरीके। जर्नल ऑफ़ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन। https://doi-org/10-29070/efvbÛ490

10. मणिकंदन, सी., और वायट, ए. (2019)। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल और संघीय ढांचे वाले प्रोत्साहनः पट्टली मक्कल काची (PMK) का मामला। कंटेंपरेरी साउथ एशिया। https://doi-org/10-1080/09584935-2019-1572070

11. नोरबू, डॉ. एम. (2026)। पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलः उत्पत्ति, चुनावी गतिशीलता और भारतीय संघवाद पर प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च। https://doi-org/10-46609/ijsser-2026-v11i02-001

12. पांडा, के. (2025). भारत में सहकारी संघवादः नीति कार्यान्वयन और वित्तीय संघवाद में अंतर–सरकारी संस्थानों की भूमिका का आकलन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग रिसर्च। https://doi-org/10-64823/ijter-2505014

13. प्रसोभ, ए. (2025). भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका। जर्नल ऑफ़ एडवांसेज इन डेवलपमेंटल रिसर्च। https://doi-org/10-71097/ijaidr-v16-i2-2029

14. साहा, टी., और डाकुआ, जी. (2024). भारत में केरल की गठबंधन राजनीति के बदलते रुझानः शुरुआत से 2016 तक। रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी। https://doi-org/10-31305/rrijm-2024-v09-n03-012

15. शर्मा, एम. (2023). भाजपा का एक–दलीय प्रभुत्वः भारतीय संघवाद में संघर्ष और सहयोग की उभरती गतिशीलता। यूरोपियन जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन एप्लाइड साइंसेज। https://doi-org/10-1177/00195561231177024

16. टिलिन, एल., और परेरा, ए. डब्ल्यू. (2017). ब्राजील और भारत में संघवाद, बहु–स्तरीय चुनाव और सामाजिक नीति। कॉमनवेल्थ एंड कम्पैरेटिव पॉलिटिक्स। https://doi-org/10-1080/14662043-2017-1327928

17. तिर्की, सी. ए. (2024). खंडित शासनः भारत में गठबंधन की राजनीति और सत्ता–साझाकरण। स्टैलियन जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एसोसिएटेड रिसर्च स्टडीज। https://doi-org/10-55544/sjmars-3-4-13

18. वनजा. (2024). भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका – एक अध्ययन। शोधकोश जर्नल ऑफ़ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। https://doi-org/10-29121/shodhkosh-v5-i1-2024-4303

❑❑❑